SUPREME COURT AS A COURT OF RECORD

As a Court of Record, the Supreme Court has two powers/ एक कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के पास दो शक्तियां हैं:

- The judgements, proceedings and acts of the Supreme Court are recorded for perpetual memory and testimony. / सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कार्यवाही और काम हमेशा याद रखने और सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।
- These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court./ इन रिकॉर्ड्स को सबूत के तौर पर माना जाता है और किसी भी कोर्ट में पेश किए जाने पर इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
- They are recognized as legal precedents and legal references./ इन्हें कानूनी मिसाल और कानूनी संदर्भ के तौर पर मान्यता दी जाती है।
- It has power to punish for contempt of court, either with simple imprisonment for a term up to six months or with fine up to Rs.2,000 or with both./ इसके पास कोर्ट की अवमानना के लिए सज़ा देने की शक्ति है, या तो छह महीने तक की साधारण कैद या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों।

POWER OF JUDICIAL REVIEW

- Judicial review is the power of the Supreme Court to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the Central and state governments. / ज्यूडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट की वह शक्ति है जिसके तहत वह केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है।

- On examination, if they are found to be violative of the Constitution (ultra-vires), they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid (null and void) by the Supreme Court. / जांच करने पर, अगर वे संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं (अल्ट्रा-वायर्स), तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (नल एंड वॉइड) घोषित कर सकता है।

CONTEMPT OF COURTS

- Contempt of Court refers to any acts or omissions that impede the functioning of a court of law in any manner. / Contempt of Court का अर्थ है ऐसे कोई भी कार्य या चूक जो किसी न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- In India, the procedures and punishments related to contempt of courts are regulated by the Contempt of Courts Act of 1971. / भारत में न्यायालय की अवमानना से संबंधित प्रक्रियाएँ और दंड Contempt of Courts Act of 1971 द्वारा विनियमित किए जाते हैं।
- As per the Act, contempt of courts can be of 2 types:/ अधिनियम के अनुसार, contempt of courts दो प्रकार की होती है:
  a. Civil Contempt: It refers to/ Civil Contempt: इसका अर्थ है:
     - Wilful disobedience to any judgment, order, writ, or other process of a court; or / किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना; या
     - Wilful breach of an undertaking given to a court / न्यायालय को दिए गए किसी उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन करना।

CONTEMPT OF COURTS

b) Criminal Contempt: It refers to the publication of any matter or doing an act that:/ Criminal Contempt: इसका अर्थ है किसी ऐसी बात का प्रकाशन या कार्य करना जिससे:

- scandalizes or lowers the authority of a court; or / न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है या उसकी अधिकारिता कम होती है; या
- prejudices or interferes with the due course of a judicial proceeding; or/ किसी न्यायिक कार्यवाही के उचित संचालन में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप होता है; या
- interferes or obstructs the administration of justice in any other manner. / या किसी भी अन्य प्रकार से न्याय के प्रशासन में बाधा या अवरोध उत्पन्न होता है।

SUMMON
“bhai aa jana”
WARRANT
“ab toh jaana hi padega”

Difference between Summons & Warrant
Summons
• Summon is Issued to call a person to court or a government office
• It is commonly Used in civil cases or for depositions, hearings, etc.
• Can be issued by courts or government agencies.
• Ignoring it may lead to contempt of court
• Summons Can be issued without a hearing, based on the court or agency's authority.
Warrant
• It is Issued to allow police to search a place or arrest someone.
• Mostly used in criminal cases to gather evidence or arrest.
• Issued only by a judge or magistrate.
• Ignoring it may lead to arrest or forced search.
• Issued only after showing probable cause in a court hearing, and needs judge's approval.

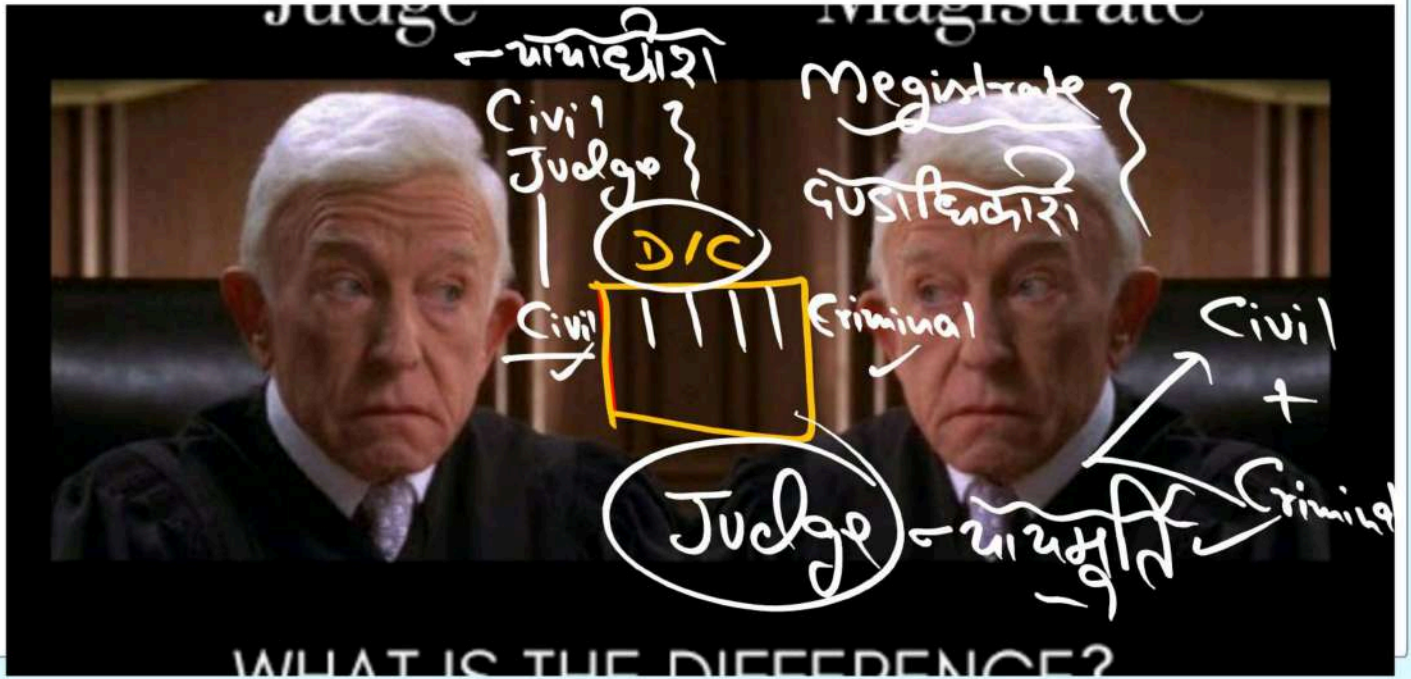

Judge Magistrate

WHAT IS THE DIFFERENCE?

COMPARISON B/W INDIAN AND AMERICAN SUPREME COURT

Indian

1. Its original jurisdiction is confined to federal cases.
2. Its appellate jurisdiction covers constitutional, civil and criminal cases.
3. It has a very wide discretion to grant special leave to appeal in any matter against the judgement of any court or tribunal.
4. It has advisory jurisdiction.
5. Its scope of judicial review is limited.
6. It defends rights of the citizen according to 'procedure established by law'
7. Its jurisdiction and powers can be enlarged by Parliament.
8. It has power of Judicial superintendence and control over state high courts due to integrated judicial system.

American

1. its original jurisdiction covers not only federal cases but also cases related to naval forces, maritime activities, ambassadors, etc.
2. Its appellate jurisdiction is confined to constitutional cases only.
3. It has no such plenary power.
4. It has no advisory jurisdiction.
5. Its scope of judicial review is very wide
6. It defends rights of the citizen according to the 'due process of law'
7. It has no such power due to double (or separated) judicial system.

COMPARISON B/W INDIAN AND AMERICAN SUPREME COURT

Indian SC

1. इसका ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन सिर्फ़ फ़ेडरल मामलों तक ही सीमित है।
2. इसका अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन संवैधानिक, सिविल और क्रिमिनल मामलों को कवर करता है।
3. इसे किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ किसी भी मामले में अपील करने के लिए स्पेशल लीव देने का बहुत बड़ा अधिकार है।
4. इसके पास एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है।
5. इसके ज्यूडिशियल रिव्यू का दायरा सीमित है।
6. यह 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अनुसार नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है।
7. इसके ज्यूरिस्डिक्शन और शक्तियों को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
8. इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियल सिस्टम के कारण इसे राज्य के हाई कोर्ट्स पर ज्यूडिशियल सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल की शक्ति प्राप्त है।

American SC

1. इसका ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन न केवल फेडरल मामलों को कवर करता है बल्कि नौसेना, समुद्री गतिविधियों, राजदूतों आदि से संबंधित मामलों को भी कवर करता है।
2. इसका अपीलीय ज्यूरिस्डिक्शन केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है।
3. इसके पास ऐसी कोई पूरी शक्ति नहीं है।
4. इसके पास कोई सलाहकार ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है।
5. न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा बहुत बड़ा है।
6. यह 'कानून की उचित प्रक्रिया' के अनुसार नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है।
7. दोहरे (या अलग) न्यायिक प्रणाली के कारण इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।

Acting Judge

- The **President** can also appoint a duly qualified person as an acting judge of a High Court when a judge of that High Court is:
- **unable to perform** the duties of his/her office due to absence or any other person
- **appointed** to act **temporarily as Chief Justice** of that High Court
- An acting judge holds office until the permanent judge resumes his/her office. However, he/she **cannot hold office after attaining the age of 62 years.**

Additional Judge

- The **President can appoint** duly qualified persons as additional judges of a High court for a temporary period **not exceeding two years** when:
- there is a temporary increase in the business of the High Court,
- there are arrears of work in the High Court.
- An additional judge **cannot hold office after attaining the age of 62 years**

Retired Judge

- The **Chief Justice of a High Court** of a State **can request a retired judge** of that High Court or any other High Court to act as a judge of the High Court of that State for a temporary period.
- The Chief Justice of a High Court of a State can do so **only with the previous consent of the President** and also of the **person to be so appointed**.
- Allowances of such a judge are determined by the President of India.
- He/she enjoys all the jurisdiction, powers, and privileges of a judge of that High Court. But, he/ she will **not otherwise be deemed to be a judge of that high court.**

कार्यवाहक न्यायाधीश

- राष्ट्र... ज के रूप में एक योग्य व्यक्ति को एक्टिंग जज के तौर पर भी नियुक्त कर सकते हैं, जब उस हाई कोर्ट का कोई जज:
- गैरमौजूदगी या किसी अन्य कारण से अपने ऑफिस का काम करने में असमर्थ हो
- उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया हो
- एक एक्टिंग जज तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि परमानेंट जज अपना पद फिर से संभाल नहीं लेता। हालांकि, वह 62 साल की उम्र के बाद पद पर नहीं रह...

अतिरिक्त न्यायाधीश

- ...नल जज के तौर पर सही क्वालिफिकेशन वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दो साल के लिए टेम्परेरी समय के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, जब:
- हाई कोर्ट के काम में टेम्परेरी बढ़ोतरी हो,
- हाई कोर्ट में काम का बैकलॉग हो।
- एडिशनल जज 62 साल की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकते।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश

- कि... फ जस्टिस उस हाई कोर्ट या किसी दूसरे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कुछ समय के लिए उस राज्य के हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
- राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसा सिर्फ प्रेसिडेंट और उस व्यक्ति की पहले से सहमति से ही कर सकते हैं जिसे इस तरह अपॉइंट किया जाना है।
- ऐसे जज के अलाउंस भारत के प्रेसिडेंट तय करते हैं।
- उन्हें उस हाई कोर्ट के जज के सभी अधिकार, शक्तियां और प्रिविलेज मिलते हैं। लेकिन, उन्हें उस हाई कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा।

JURISDICTION OF HIGH COURT

- The present jurisdiction and powers of a High Court are governed by multiple sources, including:/ हाई कोर्ट का मौजूदा अधिकार क्षेत्र और शक्तियां कई सोर्स से तय होती हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - the constitutional provisions,/ संवैधानिक प्रावधान,
  - the Letters Patent,/ लेटर्स पेटेंट,
  - the Acts of Parliament,/ संसद के अधिनियम,
  - the Acts of State Legislature,/ राज्य विधानमंडल के अधिनियम,
  - the Indian Penal Code, 1860,/ भारतीय दंड संहिता, 1860,
  - the Criminal Procedure Code, 1973, and/ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, और
  - the Civil Procedure Code, 1908./ दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908।

- The extensive jurisdiction and powers of the High Court can be classified into the following categories:/ हाई कोर्ट के व्यापक अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - Original jurisdiction/ मूल क्षेत्राधिकार
  - Writ Jurisdiction/ रिट क्षेत्राधिकार
  - Appellate jurisdiction/ अपीलीय क्षेत्राधिकार
  - Supervisory Jurisdiction/ पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

Original Jurisdiction

- Disputes relating to the election of members of Parliament and State Legislatures.
- Regarding revenue matters or an act ordered or done in revenue collection.
- Enforcement of fundamental rights of citizens.
- Cases ordered to be transferred from a subordinate court involving the interpretation of the Constitution to its own file.
- The four High Courts (i.e., Calcutta, Bombay, Madras and Delhi High Courts) have original civil jurisdiction in classes of higher value.

Writ Jurisdiction

- As per Article 226 of the Indian Constitution, the High Court is empowered to issue writs for the **enforcement of Fundamental Rights and any ordinary legal right.**
- The **writ jurisdiction** of the **High Court** is **not exclusive but concurrent with** the writ jurisdiction of the **Supreme Court.**
- However, the **writ jurisdiction of** the **High Court** is **wider than** that of the **Supreme Court**
- While the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental rights, the High Court can **issue writs for the enforcement of Fundamental Rights as well as any ordinary legal right**

Appellate Jurisdiction

- The High Court is primarily a court of appeal and **hears appeals against the judgments of Subordinate Courts functioning within the territorial jurisdiction of the State.**
- The Appellate Jurisdiction of the Supreme Court can be **classified under** the following **two heads:**

1. **Appeals in Civil Matters**
2. **Appeals in Criminal Matters**

मूल न्यायाधिकार

- ... विवाद।
- राजस्व मामलों या राजस्व वसूली में किए गए किसी कार्य या आदेश से संबंधित।
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करना।
- संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को निचली अदालत से अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश देना।
- चार हाई कोर्ट (यानी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट) के पास ज़्यादा कीमत वाले मामलों ... ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस...

रिट क्षेत्राधिकार

- ... अधिकारों और किसी भी सामान्य कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।
- हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिस्डिक्शन के साथ-साथ चलता है।
- हालांकि, हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है।
- जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी भी सामान्य कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

- हाई कोर्ट मुख्य रूप से एक अपील कोर्ट है और यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है।
- सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार क्षेत्र को इन दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है:
  1. सिविल मामलों में अपील
  2. आपराधिक मामलों में अपी...

IMPORTANT ARTICLES RELATED TO SUPREME COURT

- Article 124 : Establishment and constitution of Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन।
- Article 125 : Salaries of judges. / न्यायाधीशों के वेतन।
- Article 126 : Appointment of Acting Judges. / कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- Article 127 : Appointment of Ad-Hoc judges. / अस्थायी (Ad-Hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- Article 128 : Attendance of Retired Judges. / सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति।
- Article 129 : Supreme Court as a court of Record. / सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख का न्यायालय होगा।
- Article 130 : Seat of Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय का स्थान।
- Article 131 : Original Jurisdiction of Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र।

IMPORTANT ARTICLES RELATED TO SUPREME COURT

- Article 132 : Appellate Jurisdiction of Supreme Court (Constitutional matters). / सर्वोच्च न्यायालय का अपीली अधिकार क्षेत्र (संवैधानिक मामलों में)।
- Article 133 : Appellate Jurisdiction of Supreme Court (Civil matters). / सर्वोच्च न्यायालय का अपीली अधिकार क्षेत्र (दीवानी मामलों में)।
- Article 134 : Appellate Jurisdiction of Supreme Court (Criminal matters). / सर्वोच्च न्यायालय का अपीली अधिकार क्षेत्र (आपराधिक मामलों में)।
- Article 134A : Certificate for appeal to the Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र।
- Article 135 : Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court. / वर्तमान कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के अधिकार और शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी।

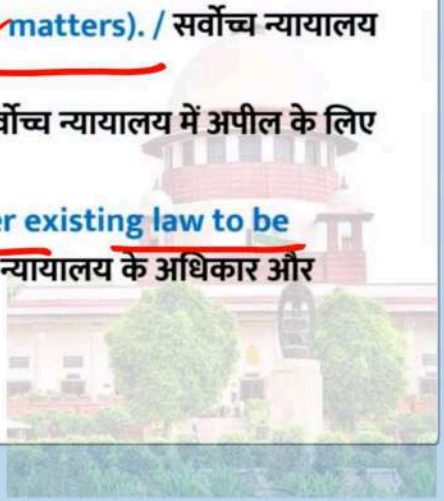

IMPORTANT ARTICLES RELATED TO SUPREME COURT

- Article 136 : Special leave to appeal by the Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति से अपील।
- Article 137 : Review of Judgements or orders by the Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की पुनर्विचार याचिका।
- Article 138 : Enlargement of Jurisdiction of the Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार।
- Article 139 : Conferment on the Supreme Court of power to issue certain writs. / सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना।
- Article 140 : Ancillary power of Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ।
- Article 141 : Law declared by Supreme Court to be binding on all courts. / सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।

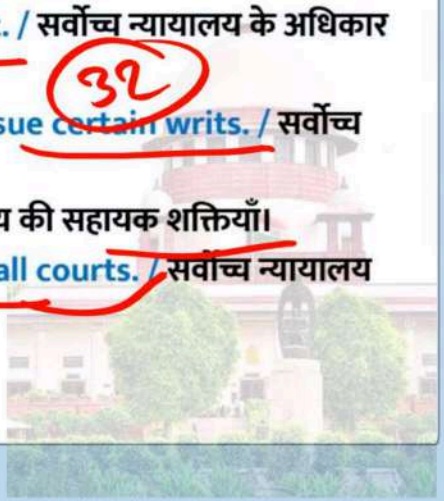

IMPORTANT ARTICLES RELATED TO SUPREME COURT

- Article 142 : Enforcement of decrees and orders. / डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन।
- Article 143 : Power of President to consult Supreme Court. / राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति।
- Article 144 : Civil and Judicial authorities to act in aid of the Supreme Court. / नागरिक एवं न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।
- Article 145 : Rules of Court etc. / न्यायालय के नियम आदि।
- Article 146 : Officers and servants and the expenses of the Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी और व्यय।
- Article 147 : Interpretation. / व्याख्या।

IMPORTANT CASE AND JUDGEMENTS

QUESTION

Practice Time

1. Disputes between two or more states come under the ___ of the Supreme Court.

दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के ___ के अंतर्गत आते हैं।

(a) Original Jurisdiction / मूल अधिकारिता

(b) Advisory jurisdiction / परामर्शाधिकारिता

(c) Appellate jurisdiction / अपीली अधिकारिता

(d) Writ jurisdiction / रिट अधिकारिता

SSC STENOGRAPHER 12/10/23

QUESTION

Art 16(4) 2021

Practice Time

2. The state of Kerala vs Leesamma Joseph case deals with __

केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ मामला __ से संबंधित है।

(a) Dowry / दहेज

(b) The economic weaker section / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

(c) Education / शिक्षा

(d) Persons with disability / दिव्यांग व्यक्तियों से

SSC CGL 2023

QUESTION

Practice Time

3. The Supreme Court of India came into existence on __

भारत का सर्वोच्च न्यायालय __ को अस्तित्व में आया।

(a) 30 January 1935 / 30 जनवरी 1935

(b) 26 January 1950 / 26 जनवरी 1950

(c) 15 August 1947 / 15 अगस्त 1947

(d) 2 October 1952 / 2 अक्टूबर 1952

28 Jan

SSC CGL 24/07/2023

QUESTION

Practice Time

4. Till which year did High Court of Delhi continue to exercise jurisdiction of Himachal Pradesh?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस वर्ष तक जारी रखा?

(a) 1969

(b) 1967

(c) 1971

(d) 1968

SSC CGL 27/07/23

QUESTION

Practice Time

5. The first High Court of India was established in the year __

भारत का पहला उच्च न्यायालय वर्ष __ में स्थापित किया गया था।

(a) 1860

(b) 1862

(c) 1867

(d) 1857

1 July 1862 - Calcutta H/C

14 Aug 1862 - Bombay H/C

15 Aug 1862 - Madras H/C

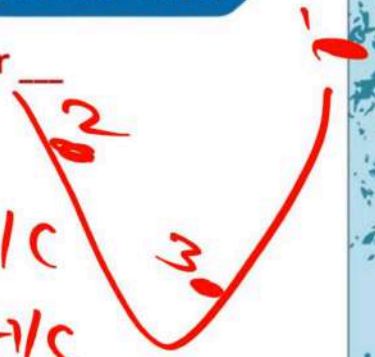

SSC MTS 03/05/23

QUESTION

Practice Time

6. In which of the following cases did the Supreme Court of India pronounce the theory of the 'Basic Structure' of the Constitution?

निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की 'मूल संरचना' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया?

(a) Kesavananda Bharti case, 1973 / केशवानंद भारती मामला, 1973

(b) Golaknath case, 1967 / गोलकनाथ मामला, 1967

(c) Minerva mill case, 1980 / मिनर्वा मिल मामला, 1980

(d) Swarn singh case, 1989 / स्वरन सिंह मामला, 1989

SSC CGL 2022

QUESTION

Practice Time

7. Which is not correct about the independence of the judiciary in our country?
हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?

(a) The judiciary has the power to penalise those who are found guilty of contempt of court. / न्यायपालिका के पास अदालत की अवमानना के दोषियों को दंडित करने की शक्ति है।

(b) The judges are financially dependent on both the executive and legislature / न्यायाधीश कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर आर्थिक रूप से निर्भर है।

(c) The constitution prescribes a very difficult procedure for removal of judges. / संविधान न्यायाधीशों को हटाने की एक बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है।

(d) The legislature is not involved in the process of appointment of Judges / न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं है।

SSC CPO 2022

QUESTION

Practice Time

8. Who amongst the following is NOT part of the Union Executive?

निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है?

(a) The Prime Minister of India / भारत के प्रधानमंत्री

(b) The President of India / भारत के राष्ट्रपति

(c) The Supreme Court of India / भारत का सर्वोच्च न्यायालय

(d) The council of Ministers / मंत्रिपरिषद

SSC CHSL 25/05/22

QUESTION

Practice Time

9. A judge of the Supreme Court can be removed on the grounds of __

सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को __ के आधार पर हटाया जा सकता है।

(a) Disrespect of the Constitution / संविधान के प्रति असम्मान

(b) Proven misbehaviour or incapacity / सिद्ध कदाचार या अक्षमता

(c) Murder charges / हत्या के आरोप

(d) Lack of knowledge / ज्ञान की कमी

SSC CGL 2022

QUESTION

Practice Time

10. A Supreme court or High Court judge can be removed by the Parliament by:

सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा किस प्रकार से हटाया जा सकता है?

(a) Simple majority / साधारण बहुमत

(b) Both simple and two third majority / साधारण एवं दो-तिहाई दोनों बहुमत से

(c) Special majority / विशेष बहुमत

(d) Two third majority / दो-तिहाई बहुमत

SSC CPO 2022

QUESTION

Practice Time

11. Which of the following qualifications should the judges of the Supreme Court have?

निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यताएँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में होनी चाहिए?

(a) He must have worked as a judge for at least 5 years in one or more High Courts continuously / उन्होंने एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष लगातार न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो।

(b) He must have been an advocate for 10 years in one or more High Courts continuously / उन्होंने एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष लगातार अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो।

(c) He must be an accomplished jurist / वे एक प्रतिष्ठित न्यायविद हों।

(d) Any of the above / उपरोक्त में से कोई भी

QUESTION

Practice Time

12. Ad hoc judges are appointed in the Supreme Court when-

सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब–

(a) Some judges go on long-term leave / कुछ न्यायाधीश लंबे अवकाश पर जाते हैं।

(b) No one is available for permanent appointment / स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता।

(c) There is an extraordinary increase in the cases pending before the court / अदालत के समक्ष लंबित मामलों में असाधारण वृद्धि हो जाती है।

(d) There is no quorum of judges for any session of the court / अदालत के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता।

QUESTION

Practice Time

13. The appointment of ad hoc judges in the Supreme Court is inspired by the judicial system of which country?

सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी (ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है?

(a) Australia / ऑस्ट्रेलिया

(b) Canada / कनाडा

(c) USA / अमेरिका

(d) France / फ्रांस

QUESTION

Deepak's Mind 2017

Practice Time

14. Against which judge of the Supreme Court, the impeachment motion brought in the Lok Sabha on 11 May, 1993 failed?

सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव विफल हुआ था?

(a) Justice Kuldeep Singh / न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह

(b) Justice V. P. Jeevan Reddy / न्यायमूर्ति वी. पी. जीवन रेड्डी

(c) Justice V. Ramaswami / न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी

(d) Justice S. P. Bharucha / न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा

QUESTION

Practice Time

15. Which of the following Chief Justices of India acted as President?

निम्नलिखित में से किस भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया?

(a) Justice S. Hidayatullah / न्यायमूर्ति एस. हिदायतुल्लाह

(b) Justice Mehar Chand Mahajan / न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन

(c) Justice P. N. Bhagwati / न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती

(d) Justice B. K. Mukherjee / न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी

QUESTION

Practice Time

16. Which language is used for judicial work in the Supreme Court?

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है?

(a) Hindi / हिन्दी

(b) English / अंग्रेज़ी

(c) Both Hindi and English / हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों

(d) Any language included in the 8th Schedule / आठवीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा

THANK
YOU